

संक्षिप्त समाचार

जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 4 की मौत, 30 घायल

जौनपुर, एजेंसी। यूपी के जौनपुर के बरसा थाना क्षेत्र स्थित शंभूराज बाजार के पास शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बदलापुर से जौनपुर की ओर आ रही एक प्राइवेट बस की स्टेयरिंग फेल हो जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत-बचाव कार्य शुरू कराया गया। सभी घायलों को नेपेड़वा सीएचसी भेज गया। घायलों में 15 की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। वहीं पुलिस ने हादसे वाली बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट बस बदलापुर के घनश्यामपुर से जौनपुर के लिए 55 सवारियों को लेकर चली थी। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे बस शंभूराज बाजार के पास पहुंची थी। इस बीच प्राइवेट बस की अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अफरातफरी मच गई। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई। 30 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां घायलों में 15 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लोगों की मानें तो बस तेज रफ्तार में थी। स्टेयरिंग फेल होने के कारण बेकाबू हो गई और पलट गई है। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।

अयोध्या, मथुरा-वृंदावन समेत यूपी के 7 शहरों में योगी सरकार स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं देने जा रही है

अयोध्या, एजेंसी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सात शहरों अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद व फिरोजाबाद में दो सालों में स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं देने जा रही है। इन शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना में न्यूनतम 250-250 करोड़ रुपये के काम कराए जाने हैं। शहरों से इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में संबंधित नगर निगमों के मंडलायुक्तों के साथ नगर आयुक्तों को निर्देश भेज दिए हैं। योगी सरकार का प्लान है कि प्रदेश के सात शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, आईटीएमएस, स्मार्ट वलास, जलान कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सीनियर केयर सेंटर, हेल्थ एटीएम, पार्क और ओपन जिम की सुविधाएं दी जाएं। इन शहरों में कुल 1750 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इन शहरों में अभी तक आधे से अधिक काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अधिकतर शहरों द्वारा प्रस्ताव ही नहीं भेजे गए। शासनादेश में कहा गया है कि अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद शहरों में वाइवार योजनाएं चिह्नित की जाएंगी। इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्रस्तावों के आधार पर शासन स्तर से पैसे दिए जाएंगे और तय समय में नगर निगमों को यह काम कराना है। शासनादेश में कहा गया है कि पहले पांच साल संबंधित नगर निगमों को काम कराने और प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए दिए जा चुके हैं, अब दो साल और दिए जा रहे हैं। इसलिए इन दो सालों में नगर निगमों में द्वारा शहर में बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कराए जाएंगे। इसमें जरूरत के आधार पर लोगों से सुझाव भी लिए जा सकते हैं।

कुते ने लिफ्ट में पड़ोसी को काटा, कोर्ट ने मालिक को सुनाई 4 महीने की कठोर सजा

मुंबई, एजेंसी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुते के काटने की घटना में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक 40 साल के व्यक्ति को उसके पालतू कुते के द्वारा पड़ोसी को लिफ्ट में काटे जाने के मामले में चार महीने की कठोर कैद और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला शहर के वली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स का है। आरोपी ऋषभ पटेल को जानबूझकर चोट पहुंचाने और पालतू जानवर के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट सुझास भीषण होने ने कहा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि आरोपी अपने ही पालतू कुते को जबरन लिफ्ट में घसीटा है। इससे साफ है कि उसे न तो अपने पालतू जानवर की हिंता थी, न ही लिफ्ट में मौजूद लोगों की। उन्होंने आगे कहा, ऐसे कृत्य के लिए अदालत बहुत अधिक नरमी नहीं बरत सकती। घटना तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुलने के समय की है, जब पीड़ित रामिक शाह, उनका डेढ़ साल का बेटा और घरेलू नौकर अनजुन सिंह चौथी मंजिल से नीचे जा रहे थे। शाह ने पटेल से अनुरोध किया कि उनका बेटा कुत्ते से उतरता है। थोड़ी देर लिफ्ट में चढ़ने से रुकने के लिए कहा। लेकिन पटेल ने इस आग्रह को नजरअंदाज करते हुए, हस्की को खींचते हुए लिफ्ट में जबरन प्रवेश कर लिया। इसके बाद हस्की ने शाह की बांह पर काट लिया। शाह के अनुसार, वह और उनका परिवार लिफ्ट से बाहर निकल गए लेकिन पटेल ने उन्हें पीछा करते हुए कहा, जो करना है कर लो। इसके बाद शाह ने अपना इलाज कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुकदमे के दौरान शाह और घरेलू नौकर अनजुन सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बयान दिया।

कांग्रेस पर फिर बरसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, कहा-

मुंबई आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की चिता की आग ठंडी भी न हुई थी, यूएस के दबाव में पाक से क्यों की बात?

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में मारे गए 180 लोगों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर दुश्मन देश पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में लोकसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का दिया बयान भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए दुबे ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया था। एक्स पर साझा उस पोस्ट में दुबे ने जुलाई 2009 में मिश्र के शर्म अल-शेख में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच हुई बैठक का जिक्र किया है और कहा है कि यह नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी।



निशिकांत दुबे ने बैठक के समय पर सवाल उठाते हुए लिखा, मुम्बई में पाकिस्तान ने हमला 26 नवंबर 2008 को किया। 180 लोग मरे व 300 घायल हुए, चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, 1 दिसंबर से बिना पाकिस्तान पर आक्रमण किए बातचीत अमेरिकी दबाव में शुरू किया या नहीं, यह वक्तव्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का है लोकसभा में? जनवरी 2009 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी या नहीं? भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत न केवल समय से पहले हुई बल्कि बाहरी ताकतों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित भी थी। उन्होंने 2009 के कई उदाहरणों का हवाला दिया जहां भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं ने कूटनीतिक बातचीत की। उन्होंने पूछ, जनवरी

2009 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी या नहीं? जून 2009 में रूस में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़रदारी से किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में मिले थे या नहीं? जुलाई 2009 में अमेरिकी दबाव में शर्मल शेख मिश्र गए थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सम्झौता किया था या नहीं? कांग्रेस पार्टी के कथित नरम रवये की भी आलोचना : 2011 में हुई एक और बड़ी आतंकी घटना का जिक्र करते हुए दुबे ने कहा कि इस तरह के हमले पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने को उजागर करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कथित नरम रवये की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, 2011 में फिर से मुंबई में विस्फोट हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके हमारा सिर ऊंचा किया, सालों बाद पाकिस्तान दहशत में है। कांग्रेस पूरी तरह से आतंकी पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। जनता जाए भाड़ में।

राजीव गांधी सरकार की भी आलोचना : इससे पहले, गुरुवार को एक पोस्ट में दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1988 में पाकिस्तान के साथ हुए कथित परमाणु सम्झौते को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

सुरक्षाबलों के एक्शन से टूटी लाल आतंक की कमर, बस्तर हुआ नक्सलमुक्त, रेड लिस्ट से भी हटा

बस्तर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले को केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। बस्तर संभाग का बस्तर नक्सलमुक्त एलडब्ल्यूई जिले की सूची से बाहर हो गया है। 1980 के दशक में बस्तर अति नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की पैर से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में फोर्स ने कब्जा जमा लिया। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार ने बस्तर को लेफ्ट विंग एक्टिविज्म से मुक्त घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ जंगल में माओवादी संगठन के महासचिव खूंखार नक्सली बसवा राजू की मौत के समाह्वर बाद यह बात सामने आई है। बता दें कि कई दशक तक नक्सलियों का मुख्य किला रहा



सुरक्षा जरूरी है। नक्सल मूवमेंट की अंडरस्टीमेंट नहीं कर सकते। दरभा के झीरम में हुआ था बड़ा हमला बता दें कि बस्तर वह जिला है, जहां से अबुझमाड़ और ओडिशा की एक बड़ी लंबी सीमा लगती थी। यहां से दरभा कोलेंग, तुलसीडीगरी, चांदमेटा की पहाड़ियों पर 2 साल पहले तक फोर्स का पहुंचना मुश्किल माना जाता था। इसी जिले

कमी आई है। बस्तर में नक्सली हिंसा पहले की तुलना में खत्म हो गया है। नक्सलियों के पास एक ही विकल्प- सैरेंडर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बीते वर्षों में सुरक्षा बलों के एक्शन, फोर्स के कैप खोलने, राज्य सरकार और स्थानीय जनता के संयुक्त प्रयासों से बस्तर में शांति बहाली हुई है। लगातार चल रहे विकास कार्य, सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रशासन की सक्रियता ने बस्तर को नक्सलवाद से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। सुरक्षा बलों के एक्शन से माओवादी संगठन बैकफुट पर है। नक्सलियों का जनाधार कमजोर हो रहा है। जल्द ही पूरे बस्तर संभाग से नक्सलियों का खाल्टा हो जाएगा।

एक ट्रक विस्फोटक लूट ले गए नक्सली, ओडिशा में हड़कंप; एनआईए ने अपने हाथ में ली जांच

सुंदरगढ़, एजेंसी। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मंगलवार को संदिग्ध माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटकों की लूट के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जांच शुरू कर दी है। उप महानिरीक्षक (डीआईजी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और एडिशनल एसपी समेत एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों ने राउरकेला का दौरा किया। एनआईए ने मंगलवार को सुंदरगढ़ जिले के बांको में पत्थर खदान में ले जाए जा रहे जिलेटेन के करीब 200 पैकेटों की माओवादियों द्वारा लूट मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी रेंज के डीआईजी ब्रजेश राय ने राउरकेला में संवाददाताओं को बताया, विस्फोटकों की लूट की जांच के लिए ओडिशा पुलिस एनआईए को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विस्फोटक सामग्री ले जा रहे ट्रक के चालक के बयान के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। डीआईजी ब्रजेश रे ने बताया, 27 मई को सूचना मिली थी कि विस्फोटकों से भरा



एक ट्रक किसी खास जगह ले जाया गया और उसे खाली किया गया। सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि एक पत्थर की खदान में विस्फोट होने वाला था। जांच करने पर पता चला कि कुछ लोगों ने विस्फोटकों से भरी एक वैन को अपने कब्जे में ले लिया है... वैन के ड्राइवर ने बताया कि यह काम पुलिस ने विस्फोटक सामग्री ले जा रहे ट्रक के चालक के बयान के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। डीआईजी ब्रजेश रे ने बताया, 27 मई को सूचना मिली थी कि विस्फोटकों से भरा

हुए डीजेली ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और घटनास्थल का विश्लेषण किया। उन्होंने जिला पुलिस को जरूरी निर्देश दिए और ऑपरेशन को मजबूत करने पर चर्चा की... मौजूदा जांच से पता चला है कि ये लोग झारखंड की सीमा से आए थे और विस्फोटकों को लूटने के बाद वापस चले गए... इस घटना के लिए एनआईए की एक टीम पहुंची है और जानकारी जुटा रही है और जिला पुलिस उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रही है...

यह लूट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारांड के जंगलों के निकटवर्ती क्षेत्र में हुई, जिसे माओवादियों का गढ़ माना जाता है। कथित तौर पर सशस्त्र बदमाशों ने ड्राइवर को बंदूक के बल पर धमकाया और पास के जंगल में गाड़ी ले जाने को कहा, जहां माओवादियों के एक समूह ने लगभग चार टन विस्फोटक लूट लिया। इस बीच, ओडिशा पुलिस ने झारखंड और सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर ओडिशा-दि ए और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है... लूट की घटना को देखते

सरकारी नौकरी के लिए फिजिकल टेस्ट देने वाले 2 लोगों की मौत, अब तक 5 गांवा चुके हैं जान

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा में सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश में जुटे दो लोगों की मौत हो गई है। खास बात है कि दोनों की वजह साफ हो सकी। पुलिस को लिए दिए गए फिटनेस टेस्ट के बाद हुई है। इसके अलावा 6 अस्थायी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब ऐसा मामला सामने आया हो। बीते दो महीनों में कई अस्थायी फिजिकल टेस्ट के दौरान जान गंवा चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के दौरान गुरुवार को गजपति जिले में 2 होमगार्ड अस्थायीयों की मौत हो गई। इनमें 24 वर्षीय सुलत मिशाल और 27 साल के दीपक पखलू का नाम शामिल है। दोनों नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। बीते दो महीनों में सरकारी नौकरी के लिए दिए फिजिकल टेस्ट के दौरान 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल, दीपक और सुलत की मौत की जांच जारी है।

पुलिस का कहना है कि मिशाल ने 10 मिनट में 2 किमी दौड़ पूरी की थी और उनका चयन अगले राउंड के लिए हुआ था। टेस्ट पूरा करने के बाद उन्होंने बैचनी होने की बात कही, जिसके चलते उन्हें गजपति जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह अपनी मां के साथ रहते थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में गजपति एसपी जतिंद कुमार पंडा ने कहा, ऑटोप्सी कराई

गई है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह साफ हो सकेगी। पुलिस को संदेह है कि मिशाल पहले ही किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गजपति में होमगार्ड पदों के लिए भर्ती की खातिर शारीरिक परीक्षण के दौरान सुलत मिशाल की मौत हो गई। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

इधर, टेस्ट में शामिल होने के बाद दीपक को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें और 6 अन्य लोगों को भी डीएचएच ले जाया गया था, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद दीपक को बेरहमपुर रेफर किया गया। शाम के समय उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों को संदेह है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है।

तौर पर अदालती कार्यवाई ना करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी विशेषज्ञों ने राज्य सरकार से कहा है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने की बजाय वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाएं। इस बावत आज को मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर अनौपचारिक रूप से चर्चा होने की संभावना है। आपत्तियों के बावजूद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा था बता दें कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने भाजपा की आपत्तियों के बावजूद पहली बार विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। भाजपा ने तब इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह बिल

संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरी बार, इस बिल को लौटाते हुए गवर्नर गहलोत ने हाल के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद 15 और 16 धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाते हैं और कोई भी सकारात्मक कार्यवाही सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आधारित होनी चाहिए। गवर्नर के आदेश में कहा गया है, "मैं कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति के विचारार्थ आश्रित करने के निर्णय पर पुनर्विचार न करने के लिए बाध्य हूँ।



रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सिद्धार्थमैया सरकार ने अब गवर्नर गहलोत के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर विचार किया है और चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संवैधानिक विशेषज्ञों ने कथित

भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे जाने संबंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया था। इससे पहले राज्यपाल गहलोत ने 16 अप्रैल को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया था लेकिन 28 मई को सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। गवर्नर के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर विचार : अब राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को इस बिल पर अगला कदम उठाने का फैसला लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों से मिलने की योजना बनाई थी, हालांकि वह बैठक स्थगित कर दी गई। टीओआई की एक

अत्याचार पीड़ितों को तत्परता से सहायता राशि दें : कलेक्टर

रीवा

कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में एफआईआर दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी तत्काल प्रकरण जनजातीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराएं। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग सहायता राशि के प्रकरण तत्परता से निराकृत कर पीड़ितों को समय पर राहत राशि प्रदान करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। पीड़ितों के राहत राशि के प्रकरणों में मानवीयता और संवेदनशीलता से कार्यवाही

सहायता राशि के 34 प्रकरणों को मिली मंजूरी



कलेक्टर ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सलाहकार समिति की प्रत्येक त्रैमास में बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कराएं। राहत राशि के प्रकरण हर सप्ताह प्रस्तुत करें। पीड़ितों को शिक्षा, स्वरोजगार, विवाह सहायता तथा

अधिनियम के प्रावधानों के तहत मिलने वाली हर संभव सहायता देने का प्रयास करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल ने बताया कि सहायता राशि के एक भी प्रकरण पुलिस थानों में लंबित नहीं हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होते ही उसे

जनजातीय कार्य विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में अनुसूचित जनजाति के 22 तथा अनुसूचित जाति के 12 पीड़ितों के राहत प्रकरणों की मंजूरी दी गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग कमलेश्वर सिंह उपस्थित रहे।

शिक्षकों के लंबित स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करें : कलेक्टर



रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने शिक्षकों के सभी लंबित स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने क्रमोन्नति, समन्वय बनाकर स्वत्वों के भुगतान सुनिश्चित कराने तथा पेंशन प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकृत करते हुए पीपीओ प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर ने गंगेव के बीईओ तथा लेखा अधिकारी को अत्यधिक संख्या में काफ़ी दिनों से लंबित प्रकरणों के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एमएस पैकरा, जिला कोषालय अधिकारी पुष्पेन्द्र शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता, सहायक संचालक राजेश मिश्रा सहित समस्त बीईओ उपस्थित रहे।

अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें

रीवा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मोटरयान अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात सभी थाना प्रभारियों से अज्ञात वाहन के दुर्घटना के सभी प्रकरण की जानकारी अनुविभागीय समिति में दर्ज कराएं। सभी एसडीएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अभिलेखों के साथ सहायता राशि के लिए प्रकरण कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करें। राहत शाखा के प्रभारी अधिकारी सात दिवस में सभी प्रकरण पूरे विवरण के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा दें। प्रकरण के साथ एफआईआर की कॉपी, पीड़ित के आश्रितों के बैंक खाता संख्या, मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सहित प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना के एक घंटे के गोल्डन पीरियड में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए लोग आगे आए। भारत सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना पीड़ित को योजना में शामिल अस्पतालों में दुर्घटना से 7 दिन की अवधि तक एक लाख 25 हजार रुपए की सहायता निशुल्क दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य

आपदा प्रबंधन की तैयारी बैठक 2 जून को

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में 2 जून को आपदा प्रबंधन की तैयारी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विभागवार समीक्षा करेंगी।

जल जीवन मिशन के कार्यों का संयुक्त सचिव ने किया स्थल निरीक्षण

रीवा। भारत सरकार की संयुक्त सचिव फरीदा एम नायक ने जल जीवन मिशन के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने इंटेकवेल तथा डब्ल्यूटीपी का भ्रमण कर प्रगतिरत कार्यों की जानकारी ली। जल जीवन मिशन अन्तर्गत रीवा बाणसागर एवं टमस समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों के निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने आवश्यक निर्देश देते हुए कार्य को गति देने की बात कही।

सीवरेंज एवं जलप्रदाय परियोजनाओं का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण

रीवा। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के रीवा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के अंतर्गत संचालित सीवरेंज एवं जलप्रदाय परियोजनाओं का निरीक्षण मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री शुक्ला मैहर नगर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जीआईएस मैपिंग कर जीटी कंस्ट्रक्शन का कार्य प्राथमिकता से आरंभ करने के भी निर्देश दिए गए। इससे पहले श्री शुक्ला ने कोठी, कोटर, जैतवारा और बिरसिंहपुर के लिए निर्माणधीन परियोजना जल प्रदाय परियोजना का निरीक्षण किया। गौरैया में प्रस्तावित इंटेक वेल के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजना के प्रमुख अवयवों में हो रही देरी अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इंटेक वेल हेतु प्रस्तावित एप्रोच

आधार पंजीयन के लिए तैनात होंगे कम्प्यूटर आपरेटर

रीवा। महिला एवं बाल विकास विभाग को भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आधार पंजीयन के लिए अधिकृत किया गया है। विभाग के सभी परियोजना कार्यालयों में स्थाई आधार पंजीयन की सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि आधार पंजीयन के लिए परियोजना कार्यालयों को आधार मशीनें, टैबलेट, मोबाइल किट आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं। आधार पंजीयन के लिए सभी परियोजना कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर तैनात किए जा रहे हैं। इसके लिए पात्र व्यक्ति 3 जून तक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्ट्रेट रीवा में आवेदन कर सकते हैं।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आज

रीवा। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आगामी 31 मई को मनाया जायेगा। मद्यपान तथा मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों एवं शराब तथा विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले दुष्परिणामों से समाज, युवाओं को अवगत कराने हेतु नशामुक्ति के लिये जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं एवं बच्चों को तम्बाकू से बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, टोन्डी, हृदय रोग आदि से बचाव करने के लिये जन जागरूकता लाना है। विभिन्न विभागों लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, पुलिस, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सहभागिता एवं जन अभियान परिषद, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी,

विकसित कृषि संकल्प अभियान में मिट्टी परीक्षण एवं नई कृषि तकनीकी पर वैज्ञानिकों का जोर



रीवा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का आरंभ 29 मई से हो चुका है। अभियान 12 जून तक संचालित होगा। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि की वैज्ञानिक तकनीकों, नवाचारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करके उनको उत्पादकता और आय को बढ़ाना है। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक दल गांवों में जाकर किसानों को नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रीवा एवं मऊगंज जिले में कृषि वैज्ञानिकों के दलों द्वारा अभियान का संचालन किया गया। रायपुर कर्जुलियान विकासखण्ड के बड़गांव, बघमाड़ा व करौंदी, विकासखण्ड

जिससे किसान उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि अनावश्यक उर्वरक उपयोग से होने वाली लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि किसान अपने खेतों से मिट्टी के नमूने सही तरीके से एकत्र करें। इसके लिए खेत के 8-10 विभिन्न स्थानों से 15 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी लेकर, उसे मिलाकर लगभग 500 ग्राम का नमूना तैयार करें। नमूना लेते समय खाद के ढेर, पेड़ों की छाया या जलभराव वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए।

कि वे अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाएं, क्योंकि यह फसल उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी परीक्षण से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा का पता चलता है,

स्टापडेम का निरीक्षण करने के मऊगंज कलेक्टर के निर्देश

रीवा। आगामी वर्षा ऋतु में संभावित जल भराव से डैम ओवरफ्लो अथवा बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों से बचाव हेतु जिले अन्तर्गत स्थित समस्त स्टाप डैमों का सतत निरीक्षण कर उन्हें समयबद्ध रूप से वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व खोले जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन द्वारा दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्टाप डैम की तकनीकी स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।

छूटे हुए क्षेत्रों में खिलाई जा रही है फाइलेरिया रोधी दवा

रीवा। जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती स्मृता नामदेव ने बताया है कि रीवा और मऊगंज जिले के फाइलेरिया से अति प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया रोधी दवा दी जा चुकी है। जिन क्षेत्रों में दवा का वितरण नहीं हो पाया था वहाँ 30 मई से दवा खिलाने का अभियान शुरू किया गया है। फाइलेरिया को समूल नष्ट करने के लिए दोनों जिलों में प्रभाविता इलाकों का चिन्हांकन करके दवाई दी जा रही है। फाइलेरिया के संभावित क्षेत्रों में संभावित रोगियों के खून के नमूने लेकर जांच कराए जाने पर पॉजिटिव

नौढ़िया ग्राम जल स्वावलंबी ग्राम के तौर पर चयनित

रीवा। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में स्वावलंबी ग्राम योजना आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संकट से निपटने के लिये विभिन्न जल संरक्षण, जल संचयन और जल के पुनर्चक्रण उपायों को लागू करना है। इस अभियान में न केवल जल को उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जायेगा बल्कि जल के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित कराया जावेगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिये जल का संरक्षण किया जा सके। कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने बताया कि जिले अंतर्गत ग्राम नौढ़िया जनपद पंचायत मऊगंज, जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण और जल आपूर्ति की दक्षता को बढ़ाने के लिए सस्ते और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उपाय किया जा सके। पुराने जल स्त्रों के पुनर्निर्माण और नई जल आपूर्ति योजनाओं को प्रारंभ करने के साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अन्तर्गत जनभागीदारी से स्त्रों के आसपास एवं अन्य उपलब्ध स्थानों पर पौधरोपण के कार्य आवश्यक रूप से किये जायेंगे। कलेक्टर ने बताया कि कार्ययोजना में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। जल गंगा यत्न में ग्रामों / ग्राम पंचायतों के वलस्तर बनाकर अधिकारियों की टीम बनाकर प्रत्येक ग्राम में जनजागरूकता हेतु



लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन

एवं

‘राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान’
अलंकरण

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर
को समर्पित डाक टिकट और सिक्का जारी



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

दतिया एवं सतना एयरपोर्ट का
लोकार्पण एवं
इंदौर मेट्रो का शुभारंभ

(गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से
सुपर कॉरिडोर 03 तक)



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

₹483 करोड़ लागत के 1271 नये अटल ग्राम सेवा सदन
(पंचायत भवन) की प्रथम किस्त का अंतरण

— प्रधानमंत्री —

नरेन्द्र मोदी

के कर-कमलों द्वारा (वर्चुअल माध्यम से)

— गरिमामयी उपस्थिति —

मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

31 मई, 2025 | पूर्वाह्न 11:00 बजे | जम्हूरी मैदान, भोपाल

नारी सशक्तिकरण में अग्रणी मध्यप्रदेश

- सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ
- शासकीय सेवा में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35% तक किया
- 5 लाख स्व-सहायता समूहों से 62 लाख ग्रामीण बहनें हुई आत्मनिर्भर
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख बहनों को मिली धुएं से मुक्ति

बेहतर होतीं वायु सेवाएं

- ₹ 60 करोड़ की लागत से 124 एकड़ में दतिया एयरपोर्ट एवं ₹ 37 करोड़ की लागत से सतना एयरपोर्ट का निर्माण संपन्न
- हवाई सुविधा से धार्मिक पर्यटन के साथ औद्योगिक विस्तार को मिलेगा बढ़ावा
- यात्रियों को मां पीतांबरा पीठ, मां शारदा और चित्रकूट धाम तक की हवाई सुविधा होगी उपलब्ध
- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के गंतव्यों तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर

इंदौर को मेट्रो रेल की सौगात

- ₹ 1520 करोड़ लागत की यलो लाइन मेट्रो 6 कि.मी. लंबे रूट पर चलेगी
- आधुनिक, सुगम और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी
- प्रति ट्रेन 900 से अधिक यात्री क्षमता के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, AI आधारित ट्रेकिंग एवं QR आधारित टिकटिंग प्रणाली से स्मार्ट होगा सफर

पंचायतों को स्थायी भवन

- प्रदेश भर में 1271 नये अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण से ग्राम पंचायतों को स्थायी भवन की सुविधा के साथ प्रशासनिक कार्य करने, बैठकें आयोजित करने एवं रिकॉर्ड प्रबंधन में सहायता मिलेगी

D-11033/25

सीधा प्रसारण

DD News

Webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh @jansamparkMP

JansamparkMP

#AhilyaBaiHolkarAt300

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक राजेन्द्र तिवारी द्वारा एस आर के प्रिंटिंग प्रेस विवि रोड खुटेही रोवा से मुद्रित कर जीडीसी के सामने उत्तरी करौदिया सीधी से प्रकाशित। संपादक-राजेन्द्र तिवारी, आर.एन.आई नं. 47589/88, डाक पंजीयन : MP/SDL/DN/-30/2015-17, दूरभाष : 09424315633, 7389444833